



2026:AHC:22624
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट – सी संख्या 2154 वर्ष 2026

महेन्द्र
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 13 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार सिंह, राम भवन सिंह
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 3/उप खंड मजिस्ट्रेट, सैदपुर, जिला गाजीपुर द्वारा दिनांक 10.09.2025 को पारित आदेश का अनुपालन करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24(2) के अंतर्गत दायर की गई कार्यवाही, जिसका संख्या कैस संख्या 6619/2025 (कंप्यूटरीकृत केस संख्या T202514290406619) है, प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें दिनांक 10.09.2025 को याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक उपरोक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

4. इस न्यायालय की समवर्ती पीठ द्वारा कई रिट याचिकाओं में, जिनमें प्रमुख रिट याचिका संख्या 35470 वर्ष 2025 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य) है, दिनांक 18.12.2025 को दिए गए निर्णय में, विधि को अच्छी तरह से स्थापित किया गया है, जिसमें प्रस्तर 44 से 46 में कुछ निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

“44. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत सीमा विवादों के त्वरित निपटारे के लिए एसडीओ को वैधानिक अर्ध-न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, साथ ही सीमांकन और कब्जे की बहाली के लिए अनिवार्य प्रवर्तन अधिकार भी दिए गए हैं। प्रवर्तन विवेकाधीन नहीं है, बल्कि प्रावधान की प्रभावशीलता का अभिन्न अंग है - प्रवर्तन में विफलता संपूर्ण त्वरित तंत्र को निरर्थक बना देती है और विधायी आशय को विफल कर देती है। तैयार किए गए व्यापक दिशानिर्देशों का उद्देश्य वैधानिक आदेशों (संहिता, 2006 की धारा 24; नियम, 2016 का नियम 22), कार्यकारी निर्देशों (साशनादेश दिनांक 16.12.2025), प्रशासनिक विधि रिद्धांतों और निष्पक्षता और सार्वजनिक व्यवस्था के संवैधानिक अनिवार्यताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला एक संरचित ढांचा प्रदान करना है। संबंधित प्रत्यर्थी, विशेष रूप से एसडीओ और कलेक्टर, विधि के अंतर्गत धारा 24 के अंतर्गत आदेशों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं।

45. उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व विभाग के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त दिशा-निर्देश राज्य के सभी राजस्व अधिकारियों तक पहुंचाए जाएं। अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने और आरसीसीएमएस प्रोटोकॉल के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाए।

46. प्रत्यर्थियों, विशेषकर संबंधित एसडीओ को निर्देश दिया जाता है कि वे इस रिट याचिका के सभी संबंधित आदेशों को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर, अनुमोदित स्थल ज्ञापन/सीमांकन आख्या के अनुसार सख्ती से निष्पादित करें, जिसमें सीमा चिहनों का निर्धारण और जहां आवश्यक हो, कब्जा बहाल करना सुनिश्चित करना शामिल है।”

5. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए संबंधित उप-खंड मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 10.09.2025 के आदेश का सख्ती से विधि के अनुसार और मीना देवी (उपरोक्त) मामले में ऊपर उद्धृत टिप्पणियों के अनुसार पालन करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2 फरवरी, 2026

सकलैन

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"